अध्याय-9

सतत विकास लक्ष्य- 3

अध्याय-9: सतत विकास लक्ष्य- 3

9.1 प्रस्तावना

सतत विकास लक्ष्य ***(एस डी जी- 3), "स्वस्थ जीवन एवं आरोग्य",*** जीवन के प्रत्येक चरण में सभी के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्य सुनिश्चित करना चाहता है। यह लक्ष्य, प्रजनन, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, संचारी, गैर-संचारी तथा प्राकृतिक रोगों, सार्वभौमिक स्वास्थ्य व्याप्ति के साथ साथ सुरक्षित, प्रभावी, अच्छी व सस्ती दवाओं और टीकों तक पहुंच सहित, सभी प्रमुख स्वास्थ्य प्रिथमिकताओं को संबोधित करता है।

उत्तराखण्ड सरकार/शासन ने सतत विकास लक्ष्यों हेतु नियोजन तथा नीति निर्धारण को प्रभावी, क्रियात्मक शोध एवं नीति प्रपत्र तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों की सहायता के लिए राज्य स्तरीय "उत्तराखण्ड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पालिसी एण्ड गुड गवर्नेंस (यू एस सी पी पी जी जी)" की स्थापना (अगस्त 2017) की है।

9.2 स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (एस आई एफ) और डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (डी आई एफ) का निरूपण

सतत विकास लक्ष्य की प्रगति की निगरानी और माप के लिए, राज्य सरकार को संबध विभागों के परामर्श से स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (एस आई एफ) और डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (डी आई एफ) तैयार करना था जिसमें नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (एन आई एफ) एक आधार के रूप में काम करेगा। तदनुसार, राज्य सरकार ने क्रमशः वर्ष 2020 और 2019 में स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (एस आई एफ) और डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (डी आई एफ) प्रकाशित किया। राज्य ने स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (एस आई एफ) तैयार किया जिसमें 45 संकेतक शामिल हैं (33 नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क से अपनाए गए और शेष 12 राज्य द्वारा स्वयं तैयार किए गए हैं ताकि लक्ष्य 3.1, 3.2 व 3.3 की बेहतर निगरानी की जा सके)। डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (डी आई एफ) में 9 संकेतक शामिल हैं (जनपद में एन आई एफ से 4, एस आई एफ से 5) ***(परिशिष्ट-9.1)***।

9.3 उत्तराखण्ड सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट की स्थिति (आँकड़ा संकलन व प्रसार)

नीति आयोग द्वारा जारी एस डी सी इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट 2018 में प्रावधान है, कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सतत विकास लक्ष्य

की दिशा में उनकी प्रगति का आकलन करने में उपयोगी हो सकता है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

क. राज्य सरकार ने क्रमशः वर्ष 2020 एवं 2019 में स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (एस आई एफ और डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (डी आई एफ) प्रकाशित किया।

ख. राज्य में, 45 स्टेट इंडिकेटर विकसित किए गए। हालांकि, उत्तराखण्ड एस डी जी इंडेक्स डैशबोर्ड केवल नौ संकेतकों पर आधारित है जो दर्शाता है कि सतत विकास उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की निगरानी आंशिक/अपूर्ण थी।

ग. डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (डी आई एफ) में सतत विकास लक्ष्य-3 के लिए नौ संकेतक हैं और उत्तराखण्ड एस डी जी इंडेक्स डैशबोर्ड में सभी नौ संकेतकों से संबन्धित आकड़े प्रदर्शित करता है।

9.4 स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार

नीचे दिए गए विवरण पट संख्या 9.1 से स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में संस्थागत प्रसवों, पूर्ण टीकाकरण, प्रसवपूर्व देखभाल सेवाओं का उपयोग और बच्चों की जाँच की दरों में काफी वृद्धि देखी गई है, यह प्रगति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन एच एम) के अंतर्गत योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और सावधानीपूर्वक किए गए प्रयासों का परिणाम है।

चार्ट-9.1: स्वास्थ्य संकेतक

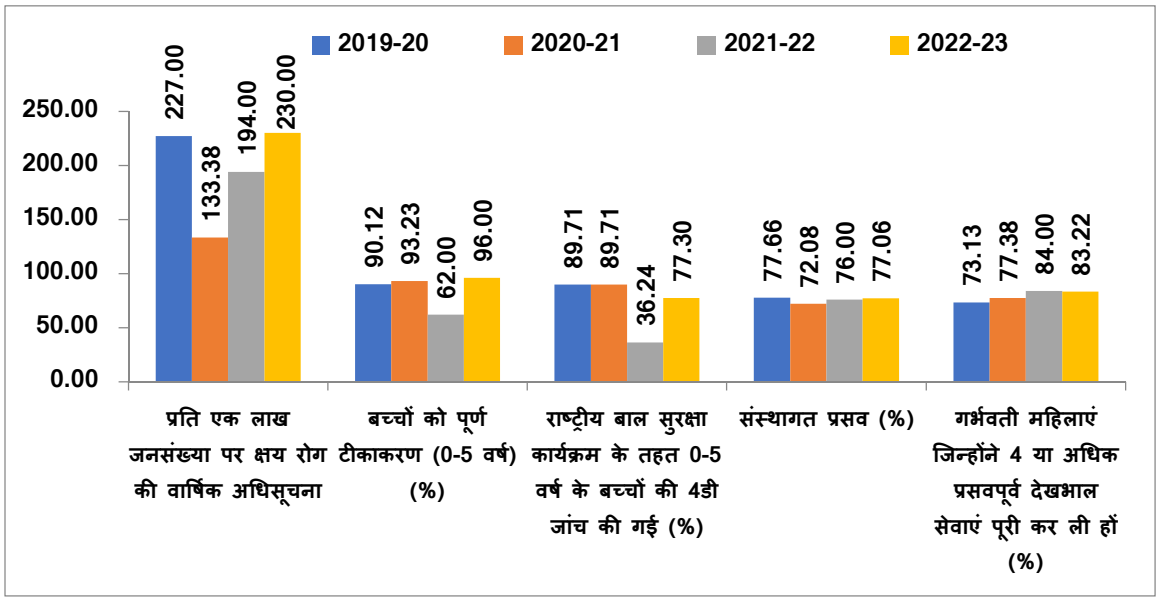

स्रोत: उत्तराखण्ड एस डी जी डैशबोर्ड।

आच्छादित की गई योजनाओं के प्रदर्शन के आधार पर संकेतकों के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सकता है जिस पर इस प्रतिवेदन में पृथक से चर्चा की गई है

9.5 हस्तक्षेप एवं समन्वय

सेंटर फॉर पब्लिक पालिसी एण्ड गुड गवर्नेंस (सी पी पी जी जी) द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण के लिए किए गए प्रयासों, उनकी उपलब्धि और राज्य में पाई गई कमियों का उल्लेख निम्नलिखित है:

- **संवेदीकरण यानी सतत विकास लक्ष्य से संबंधित जागरूकता नेतृत्व की वृद्धि:** राज्य/जिला/स्थानीय स्तरों, सिविल सोसाइटी संगठनों और समुदायों पर अधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए राज्य को अपनी स्वयं की कार्यनीतियां बनानी पड़ीं। सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध आकड़ों के विश्लेषण और सी पी पी जी जी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान बैठकों और कार्यशालाओं के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता की गई थी ***(परिशिष्ट-9.2)***। सी पी पी जी जी ने उस अवधि के दौरान विजन 2030, एस आई एफ और डी आई एफ, एस डी जी जनपदीय प्रोफ़ाइल, एस डी जी डैशबोर्ड और होलोग्राम जैसी विभिन्न आई ई सी सामग्री भी बनाई। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड के एस डी जी मिशन में भाग लेने के लिये एन जी ओ, शैक्षणिक संस्थानों आदि जैसे विभिन्न हितधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए सी पी पी जी जी स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाया गया था।
- **स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (एस आई एफ और डी आई एफ):** राज्य सरकार ने शासकीय विभागों के परामर्श से स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (एस आई एफ) और डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (डी आई एफ) तैयार किया।
- **डैशबोर्ड का संचालन:** राज्य सरकार को डैशबोर्ड को सक्रिय करना था और किसी भी समय सतत विकास लक्ष्य की समीक्षा के लिए डैशबोर्ड उपयोग करना था।

डैशबोर्ड को सतत विकास लक्ष्य समीक्षा के लिए माह अक्टूबर 2021 से सक्रिय किया गया था|

- **जिलों का श्रेणीक्रम:** राज्य सरकार सतत विकास लक्ष्य प्रदर्शन पर जिलों की आवधिक, अधिमानतः वार्षिक, श्रेणीक्रम शुरू करेगी। सी पी पी जी जी ने उत्तराखण्ड सतत विकास लक्ष्य से संबन्धित डिस्ट्रिक्ट सूचकांक तैयार किया और राज्य में जिलों का श्रेणीक्रम/प्रदर्शन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/ पोर्टल सतत विकास लक्ष्य निगरानी उपकरण पर नियमित रूप से अद्यतन कर रहा है। राज्य ने वर्ष 2015-16 से राज्य डैशबोर्ड पर अपनी जिला श्रेणीक्रम तैयार की है (जिला श्रेणीक्रम के लिए **प्रस्तर-9.3** देखें)।
- **साझेदारी का निर्माण:** राज्य को डैशबोर्ड विकसित करने के लिए विशेषज्ञ/ तकनीकी एजेंसी के साथ साझेदारी करनी पड़ी। सितंबर 2019 में, उत्तराखण्ड ने राज्य की विकास योजना को विजन 2030 के साथ संरेखित करने के लिए यू एन डी पी के साथ सहयोग किया। यू एन डी पी के अलावा, राज्य ने कई संगठनों के साथ सहयोग किया है जैसा कि ***परिशिष्ट-9.3*** में विस्तृत है।
- **चरण-समीक्षा तंत्र:** राज्य सरकार को यथासंभव द्विवार्षिक आधार पर मुख्य सचिव/ मुख्यमंत्री स्तर पर सतत विकास लक्ष्य समीक्षा तंत्र स्थापित करना था। सी पी पी जी जी की स्थापना के दौरान इसका प्रस्ताव रखा गया था और सतत विकास लक्ष्य से संबंधित कार्यों के लिये राज्य सरकार द्वारा छह राज्यों का कार्य समूहों (एस डब्ल्यू जी) का गठन (अप्रैल 2018) किया गया था।

9.6 निष्कर्ष

जिला स्तर पर केवल नौ संकेतकों के आंकड़े उपलब्ध थे, इसलिए शेष संकेतकों की निगरानी नहीं की जा रही थी। इसके अलावा, एस डी जी इंडेक्स डैशबोर्ड, 45 के स्थान पर केवल नौ संकेतकों के आकड़े एकत्रित करता है। हालांकि, वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान बैठकों और कार्यशालाओं के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा की गई।

9.7 अनुशंसा

शासन एस डी जी- 3 के तहत लक्ष्यों और संकेतकों की निगरानी के लिए अधिक संकेतको को शामिल करने पर विचार कर सकता है।

देहरादून
दिनाँक: 17 अगस्त 2024

(प्रवीन्द्र यादव)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनाँक: 17 सितम्बर 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक